

सत्यमेव जयते

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

साप्ताहिक सूचना पत्र

दिनांक 13.11.2026 से 20.11.2026

11वाँ संस्करण

सभी संस्करण यहाँ पढ़ें:

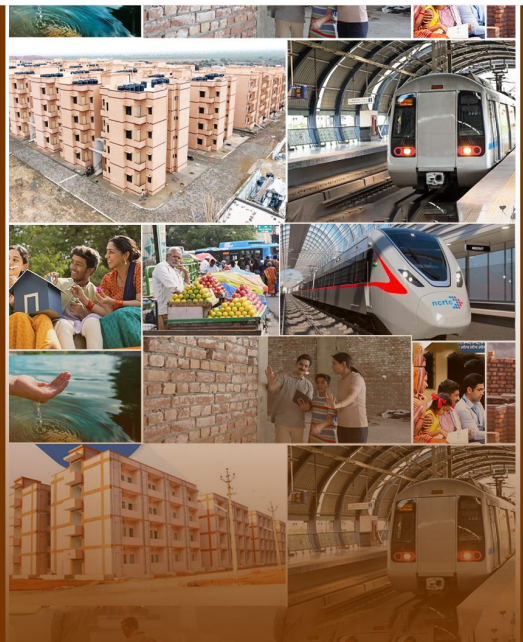

श्री मनोहर लाल

माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. **SVANidhi** का अर्थ है **अपनी पूंजी, अपना उद्यम** और आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़े होना: केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल

2. **NBCC के 67 वर्ष**: राष्ट्र निर्माण, उत्कृष्टता और श्रमजीवियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता

3. **NCRTC ने शुरू की नमो भारत सुपरफास्ट सेवा**; आनंद विहार से गाज़ियाबाद सिर्फ 8 मिनट और बेगमपुल 36 मिनट में पहुंच सकेंगे यात्री

4. **विश्व शौचालय दिवस** पर MoHUA की पहल, शहरी सार्वजनिक स्वच्छता एवं नागरिक सहभागिता को बढ़ावा

5. छठ के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह नियत समय से जल्दी शुरू

6. **HUDCO** ने जारी की **ESG रिपोर्ट 2025–26**, सतत एवं सुदृढ़ शहरों के वित्तपोषण पर जोर

साप्ताहिक सूचना पत्र

13.11.2026 से 20.11.2026

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

20 नवंबर, 2026

SVANidhi का अर्थ है अपनी पूंजी, अपना उद्यम और आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़े होना: केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल





"SVANidhi का अर्थ है अपनी पूंजी, अपना उद्यम और आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़े होना। सरकार केवल एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाती है," यह बात केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के अवसर पर कही, उन्होंने योजना की मूल भावना अर्थात विश्वास, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।

मंत्री महोदय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पीएम SVANidhi योजना ने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। इस योजना के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन लोगों पर भरोसा जताया गया है, जो परंपरागत रूप से औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से वंचित रहे हैं।

वर्ष 2020 में शुरू हुई इस योजना ने छः सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके तहत लगभग 81 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को 1.21 करोड़ से अधिक ऋणों के माध्यम से लगभग ₹20,000 करोड़ वितरित किए गए हैं। योजना के लाभार्थियों में लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि करीब 70 प्रतिशत लाभार्थी समाज के वंचित वर्गों से आते हैं। यह योजना समावेशी शहरी विकास को सशक्त बनाने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

श्री मनोहर लाल ने सभी लाभार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।





Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

15 नवंबर, 2026

NBCC के 67 वर्ष: राष्ट्र निर्माण, उत्कृष्टता और श्रमजीवियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता





NBCC (इंडिया) लिमिटेड ने 15 नवंबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में अपना 67वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर श्री मनोहर लाल, माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री एवं विद्युत मंत्री; श्रीमती डी. तारा, सचिव, राजधानी विकास विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; डॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी तथा श्री आर. वेंकटरमणि, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय एवं आम्रपाली परियोजनाओं के कोर्ट रिसीवर उपस्थित रहे। श्री तोखन साहू, माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएँ दीं।

समारोह में एनबीसीसी की 67 वर्षों की विश्वास, उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण की यात्रा का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंत्रालय एवं एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, अतिथि और उनके परिवारजन उपस्थित रहे। मेधावी विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया, जो कंपनी की विरासत और देश के अवसंरचना विकास में योगदान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत एनबीसीसी ने दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित विभिन्न परियोजना स्थलों, जिनमें WTC नौरोजी नगर, नेताजी नगर और आम्रपाली (Aspire) शामिल हैं, पर श्रमजीवियों के लिए भंडारों का आयोजन किया। सरोजिनी नगर पुनर्विकास परियोजना में कंबल वितरण एवं स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। इसी प्रकार की पहलें गुडीवाड़ा, आंध्र प्रदेश की उच्च न्यायालय परियोजना, एनवीएस भद्राद्री कोठागुडेम, तेलंगाना तथा गोवा, ओडिशा और गोरखपुर स्थित परियोजना स्थलों पर भी आयोजित की गईं। इन पहलों के माध्यम से एनबीसीसी ने अपने कार्यबल के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके कल्याण एवं खुशहाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

16 नवंबर, 2026

NCRTC ने शुरू की नमो भारत सुपरफास्ट सेवा; आनंद विहार से गाज़ियाबाद सिर्फ 8 मिनट और बेगमपुल 36 मिनट में पहुंच सकेंगे यात्री





दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए NCRTC ने नमो भारत सुपरफास्ट सेवा शुरू की है। इन सेवाओं के माध्यम से यात्री आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज 8 मिनट, गाजियाबाद से बेगमपुल 28 मिनट और आनंद विहार से बेगमपुल केवल 36 मिनट में तय कर सकेंगे। वहीं, पूरे कॉरिडोर की यात्रा 50 मिनट से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी।

तेज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव कॉरिडोर के केवल पांच प्रमुख स्टेशनों—सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम पर होगा।

सुबह दोनों टर्मिनल स्टेशनों से दो-दो सुपरफास्ट ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। सराय काले खां और मोदीपुरम से ये ट्रेनें सुबह 8:00 बजे और 8:30 बजे रवाना होती हैं। इसी प्रकार, शाम को दोनों दिशाओं में दो-दो ट्रेनें 6:00 बजे और 6:30 बजे संचालित की जा रही हैं।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

19 नवंबर, 2026

विश्व शौचालय दिवस पर MoHUA की पहल, शहरी सार्वजनिक स्वच्छता एवं नागरिक सहभागिता को बढ़ावा



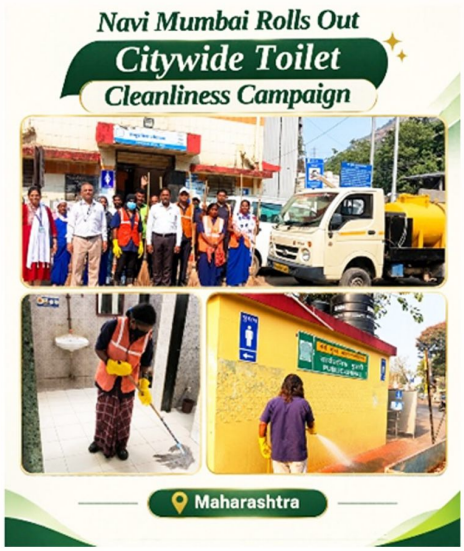



सुरक्षित स्वच्छता, शौचालयों तक सभी की पहुँच तथा स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों के महत्व को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 19 नवंबर को 'विश्व शौचालय दिवस' मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यह दिवस प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ, सुरक्षित, कार्यशील और समावेशी शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के सामूहिक संकल्प को दोहराने का अवसर है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों (CTs/PTs) को स्वच्छता अभियानों और शहरी विकास पहलों की आधारशिला के रूप में प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। इसके लिए FACES मानकों—कार्यक्षमता (Functionality), सुगमता (Accessibility), स्वच्छता (Cleanliness), पर्यावरण-अनुकूलता (E-co-friendliness) और सुरक्षा (Safety)—पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में नई शौचालय सुविधाओं का उद्घाटन, मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, संचालन और रखरखाव व्यवस्था को मजबूत करना, सार्वजनिक ऑडिट, स्वच्छता जागरूकता और नागरिक सहभागिता जैसी गतिविधियाँ आयोजित करने का सुझाव दिया गया।

विश्व शौचालय दिवस पर देशभर के शहरों और कस्बों में सुरक्षित, स्वच्छ एवं समावेशी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नागरिक-केंद्रित पहलें आयोजित की गईं। तेलंगाना के मेटपल्ली में एक आकांक्षी सार्वजनिक शौचालय (Aspirational Public Toilet) का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वच्छता बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाना और सभी के लिए सुलभ सुविधाएँ सुनिश्चित करना है। इंदौर में 'टॉयलेट फेस्ट' के माध्यम से सार्वजनिक स्वच्छता को जनभागीदारी के उत्सव के रूप में मनाया गया। इसमें स्वच्छ शौचालय अभियान, स्वच्छ रंगोली और नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियों के जरिए सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया। नवी मुंबई में नागरिकों के बीच स्वच्छता जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए शहरव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं, रामगढ़ छावनी परिषद ने थाना चौक स्थित सार्वजनिक शौचालय में विशेष स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण अभियान आयोजित किया और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से सार्वजनिक शौचालयों को स्वच्छ बनाए रखने को साझा नागरिक जिम्मेदारी के रूप में रेखांकित किया।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

16 नवंबर, 2026

छठ के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह नियत समय से जल्दी शुरू

छठ पूजा के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों के दिल्ली लौटने को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 18 से 22 नवंबर 2026 तक मेट्रो सेवाएं निर्धारित समय से पहले शुरू करने की विशेष व्यवस्था की है, ताकि यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर ब्लू और पिंक लाइन तथा नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर येलो लाइन की सेवाएं सुबह 5:15 बजे से उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, राजीव चौक और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिससे यात्रियों को रेड, ग्रीन और वायलेट लाइनों सहित अन्य मेट्रो लाइनों से निर्बाध कनेक्टिविटी मिल सके।

छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेट्रो सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4:30 बजे शुरू की गई थीं, जबकि सामान्य दिनों में सेवाएं सुबह 6:00 बजे शुरू होती हैं।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
सत्यमेव जयते

19 नवंबर, 2026

HUDCO ने जारी की ESG रिपोर्ट 2025–26, सतत एवं सुदृढ़ शहरों के वित्तपोषण पर जोर

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO) ने 17 नवंबर 2026 को वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अपनी ESG रिपोर्ट जारी की। "आज सतत शहरों का वित्तपोषण, कल के लिए सुदृढ़ भविष्य का निर्माण" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट का विमोचन HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री संजय कुलश्रेष्ठ ने निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

HUDCO के 'सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता' के दर्शन पर आधारित यह रिपोर्ट वित्तपोषण गतिविधियों के पारंपरिक प्रकटीकरण से आगे बढ़ते हुए पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (ESG) के तीन प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत वित्तपोषण एवं पहलों के वास्तविक परिणामों और प्रभावों के आकलन पर केंद्रित रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है।

रिपोर्ट में पर्यावरणीय रूप से सतत विकास के प्रति HUDCO की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है, जिसमें हरित, संसाधन-कुशल एवं जलवायु-अनुकूल शहरी अवसंरचना को बढ़ावा देना; लोगों को सशक्त बनाकर तथा समुदायों को मजबूत करते हुए सामाजिक समावेशन एवं समानता सुनिश्चित करना; और संस्थागत जवाबदेही, सुदृढ़ ESG ढाँचे एवं नैतिक कार्यप्रणालियों के माध्यम से सुशासन को प्रोत्साहित करना शामिल है।

31 मार्च 2026 तक ₹21,237.72 करोड़ के हरित परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के साथ, जो HUDCO के कुल ऋण पोर्टफोलियो का 13.21% है, HUDCO नवीकरणीय ऊर्जा, किफायती आवास, सतत जल प्रबंधन, स्वच्छ परिवहन एवं जलवायु-अनुकूल अवसंरचना के वित्तपोषण के माध्यम से सतत शहरी विकास को निरंतर बढ़ावा दे रहा है।

उत्तरदायी वित्तपोषण, सुदृढ़ ESG कार्यप्रणालियों और मापनीय परिणामों पर विशेष ध्यान देते हुए HUDCO बेहतर आवासीय परिवेश के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा सतत, सुदृढ़ एवं समावेशी शहरों के निर्माण के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता निरंतर आगे बढ़ा रहा है।



Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

भारत एकता टाइम्स
(19 नवंबर, 2026)

पीएम स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर हो रहे पथ विक्रेता



उत्तर प्रदेश में मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शहरी विकास को समावेशी बनाने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (पीएम स्वनिधि) इन प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी दुकानदारों, ठेला लगाने वाले छोटे कारोबारियों और अन्य पथ विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराकर उनके स्वरोजगार को मजबूती दी जा रही है। योजना ने छोटे व्यापारियों के लिए औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने और आत्मसम्मान के साथ जीवनयापन करने के नए अवसर खोले हैं। मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम स्वनिधि योजना इसी सोच के अनुरूप शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, चाय-नाश्ते की दुकान चलाने वाले, मोची, नाई और अन्य छोटे कारोबारी स्वनिधि अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनका व्यवसाय न केवल परिवारों की आजीविका का साधन है, बल्कि आम नागरिकों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। ऐसे में उन्हें समय पर पूंजी उपलब्ध होना उनके कारोबार की निरंतरता और विस्तार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जून, 2020 को शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराकर उनके व्यवसाय को पुनर्जीवित करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के पुनर्गठित स्वरूप में ऋण की सीमा बढ़ाई गई है। इसके अंतर्गत पहली किस्त में 15,000 रुपये तक, दूसरी किस्त में 25,000 रुपये तक और तीसरी किस्त में 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पिछली किस्त का समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थी अगली किस्त के लिए पात्र बनते हैं। इससे छोटे कारोबारियों को अपनी जरूरतों के अनुसार धीरे-धीरे कारोबार बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन विकसित करने का अवसर मिलता है।

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पथ विक्रेता लाभान्वित हो रहे हैं। अक्टूबर, 2026 तक प्रदेश में 16.62 लाख लाभार्थियों ने पहली किस्त, अप्रैल 2026 तक 5,70,586 लाभार्थियों ने दूसरी किस्त और 1,07,293 लाभार्थियों ने तीसरी किस्त का ऋण प्राप्त किया है। 30वें पीएम80 स्वनिधि योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के छोटे कारोबारियों को पूंजी उपलब्ध कराने और उन्हें औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मा. मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नगर विकास विभाग और नगरीय निकायों के माध्यम से लाभार्थियों को योजना से जोड़ने, पात्र पथ विक्रेताओं की पहचान करने तथा बैंकिंग प्रक्रिया में सहयोग देने पर जोर दिया जा रहा है। इससे छोटे दुकानदारों को कारोबार के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। वे इस धनराशि का उपयोग दुकान के लिए सामान खरीदने, व्यापार में आवश्यक सामग्री जुटाने और अपने व्यवसाय को नियमित रूप से संचालित करने में कर सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छोटे व्यापारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी माध्यम है। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए योजना में नियमित लेनदेन पर कैशबैक की सुविधा दी गई है। इससे पथ विक्रेताओं को यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यम अपनाने, भुगतान का बेहतर रिकॉर्ड रखने और आधुनिक व्यापारिक व्यवस्था से जुड़ने में सहायता मिलती है।

योजना के पुनर्गठित स्वरूप में दूसरी किस्त का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए यूपीआई से जुड़ा क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों से आगे नगरों और अवसाय के विकसित होते क्षेत्रों तक चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। ऋण सुविधा, डिजिटल प्रोत्साहन और वित्तीय समावेशन के ये प्रयास छोटे कारोबारियों के लिए आर्थिक अवसरों का दायरा बढ़ाते हैं।

पीएम स्वनिधि योजना का व्यापक महत्व इस बात में है कि इससे छोटे कारोबारियों को अपनी मेहनत और कौशल के बल पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कारोबार के लिए पूंजी उपलब्ध होने से वे अपने व्यवसाय की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। वित्तीय आय और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने में भी सहायता मिलती है। साथ ही, छोटे व्यापारियों के कारोबार में वृद्धि स्थानीय बाजारों, आपूर्ति व्यवस्था और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है।

मा. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ बड़े उद्योगों और प्रतिष्ठानों तक ही सीमित न रहे, बल्कि छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों और स्वरोजगार परियों तक भी पहुंचे। पीएम स्वनिधि योजना इसी समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

यह योजना छोटे कारोबारियों को केवल ऋण नहीं देती, बल्कि उन्हें आर्थिक आत्मविश्वास, वित्तीय पहचान और भविष्य में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करती है। पीएम स्वनिधि योजना उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने, छोटे व्यापारियों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने और आत्मनिर्भर शहरी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

लेखक - प्रवीण मालवीय

समाजा
(17 नवंबर, 2026)

पीएम स्वनिधि सम्मान 2026 के लिए पश्चिम बंगाल और दुर्गापुर नगर निगम का चयन

स्ट्रीट वेंडरों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए किए गए कार्यों को मिली राष्ट्रीय पहचान, 20 नवंबर को नई दिल्ली में मिलेगा सम्मान



कोलकाता: पश्चिम बंगाल और दुर्गापुर नगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से यह सम्मान 20 नवंबर को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रदान किया जाएगा।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव ईशा कालिया ने 16 नवंबर को पश्चिम बंगाल के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को भेजे पत्र में इसकी जानकारी दी। पत्र में योजना के सफल क्रियान्वयन में राज्य और दुर्गापुर नगर निगम के योगदान की सराहना की गई है।

पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने पुरस्कार समारोह में राज्य और शहरी स्थानीय निकायों की ओर से दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शहरी विकास एवं नगर मामलों के विभाग, दुर्गापुर नगर निगम और सूडा को बधाई दी है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडरों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की।

दैनिक भास्कर
(19 नवंबर, 2026)

20 नवंबर को दिल्ली में आयोजित समारोह में किया जाएगा सम्मानित

पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मप्र नंबर वन, बड़े शहरों में भोपाल चौथा

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के सफल क्रियान्वयन में मप्र लगातार देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 20 नवंबर को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में मप्र समेत तीन नगरीय निकायों इंदौर, सारणी और बालाघाट को सम्मानित किया जाएगा। मप्र में योजना के तहत 10.87 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ दिया गया है।

इंदौर देशभर में पहले स्थान पर... मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण वितरित कर देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं भोपाल नगर निगम ने 1,39,262 ऋण वितरित कर चौथा स्थान पाया है। मेजर सिटी श्रेणी (1 से 10 लाख जनसंख्या) में उज्जैन नगर निगम ने 59,538 ऋण वितरित कर देश में तीसरा स्थान हासिल किया।

नवभारत टाइम्स
(14 नवंबर, 2026)

शालीमार बाग में बनेगा भारत मंडपम् और यशोभूमि जैसा कन्वेंशन सेंटर

Poonam.Gaur
@timesofindia



दिल्ली को मिलेगा तीसरा बड़ा कन्वेंशन सेंटर

2.44 एकड़ जमीन पर DDA बनाएगा कन्वेंशन सेंटर

■ **नई दिल्ली :** दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बड़े सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, व्यापारिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भारत मंडपम् और यशोभूमि जैसा नया भव्य कन्वेंशन सेंटर विकसित करने की तैयारी है। यह दिल्ली का तीसरा बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। डीडीए शालीमार बाग डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सी और डी ब्लॉक में करीब 2.44 एकड़ जमीन पर इसे विकसित करेगा। इसके लिए करीब 9,882.63 वर्गमीटर जमीन 55 साल के लाइसेंस पर एजेंसी को दी जाएगी। जमीन का मालिकाना हक डीडीए के पास ही रहेगा, जबकि चयनित निजी एजेंसी निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी देखेगी। एजेंसी का चयन लाइसेंस फीस के आधार पर किया जाएगा। जमीन का मौजूदा लैंड यूज कमर्शल है। फिलहाल यह खाली है। 15,944.6 वर्गमीटर तक फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की अनुमति होगी। ग्राउंड कवरेज 50 फीसदी रखा गया है। ऊंचाई पर सामान्य प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसके लिए संबंधित वैधानिक एजेंसियों से मंजूरी लेनी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से 355 मीटर तक हो सकती है। पार्किंग के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंटर की व्यापक योजना के तहत तीन ईसीएस का प्रावधान है। निर्माण मास्टर प्लान दिल्ली-2047 और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज-2016 के नियमों के अनुसार होगा।

डीडीए के अनुसार, 16 नवंबर को इच्छुक कंपनियों और अन्य पक्षों के साथ बैठक होगी। 17 नवंबर तक सवाल भेजे जा सकेंगे और 26 नवंबर तक उनके जवाब दिए जाएंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर है। इसके बाद डीडीए विस्तृत प्रस्ताव (RFP) जारी कर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

अमर उजाला
(19 नवंबर, 2026)

यशोभूमि से गुरुग्राम तक मेट्रो का सफर होगा आसान, आठ नए कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव

फेज-5बी के तहत सात कॉरिडोर को दिल्ली सरकार की मंजूरी, केंद्र की स्वीकृति का इंतजार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले वर्षों में आवागमन और सुलभ हो सकता है। दिल्ली मेट्रो के प्रस्तावित फेज-5बी के तहत आठ नए कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी है। इन कॉरिडोर पर कुल 65 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें द्वारका स्थित यशोभूमि से गुरुग्राम के राजीव चौक तक मेट्रो कनेक्टिविटी देने वाला कॉरिडोर भी शामिल है। इससे आसपास बसी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पालम, नजफगढ़ और मथुरा विहार जैसे इलाकों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना है।

फेज-5बी के तहत आठ कॉरिडोर का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इनमें यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 से गुरुग्राम के राजीव चौक तक का कॉरिडोर भी शामिल है। इसके बनने से द्वारका और गुरुग्राम के बीच सफर करने वाले यात्रियों को सीधी मेट्रो सुविधा मिल सकेगी। खासतौर पर यशोभूमि आने-जाने वाले लोगों और गुरुग्राम में काम करने वाले यात्रियों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है।

अन्य सात कॉरिडोर को दिल्ली सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और अब इन्हें केंद्र सरकार की स्वीकृति का इंतजार है। इनमें धांसा बस स्टैंड (नजफगढ़)-नांगलोई, केंद्रीय सचिवालय-किशनगढ़, समयपुर बादली-नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉरिडोर पल्ला-पालम, जोर बाग-मिठापुर, मथुर विहार फेज-जीरो-सबसे पार्क और केशवपुरम-रोहिणी सेक्टर-34 कॉरिडोर शामिल हैं।

यात्री दिल्ली समेत कई इलाकों के यात्रियों को मिलेगी राहत : इन कॉरिडोर के निर्माण से मेट्रो की पहुंच ऐसे इलाकों तक बढ़ेगी, जहां अभी यात्रियों को नजदीकी मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए दूसरे सार्वजनिक परिवहन साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। नजफगढ़ से नांगलोई और समयपुर बादली से नरेला तक मेट्रो का विस्तार होने से बाहरी दिल्ली के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, पालम, मिठापुर और रोहिणी के नए इलाकों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी।



धांसा बस स्टैंड-नांगलोई कॉरिडोर में होंगे नौ स्टेशन

11.9 किमी लंबे पल्ला बस स्टैंड (नजफगढ़)-नांगलोई कॉरिडोर में जोर बाग, एनएटीएम, रघोना, बक्करवाला, बापरोला, दीपाली कलां और नजफगढ़ एक्सटेंशन के निवासियों को मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से इस मार्ग की शुरुआत में साढ़े तिरए नए कार्यालय के अनुसार, इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर नौ स्टेशन होंगे। नांगलोई और धांसा बस स्टैंड पर इंटरचेंज की सुविधा भी मिलेगी।

कॉरिडोर से जुड़ेंगे जेएनयू और पीएम म्यूजियम

15.9 किलोमीटर लंबे केंद्रीय सचिवालय-किशनगढ़ कॉरिडोर में यात्रियों को नए मेट्रो मार्ग, आर्के पुरम सेक्टर-1 और सेक्टर-7, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और प्रधान मिनिस्टर्स म्यूजियम तक पहुंचने में सुविधा होगी। इस कॉरिडोर पर 10 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें नौ भूमिगत होंगे। केंद्रीय सचिवालय, मोती बाग, आर्के पुरम और किशनगढ़ में इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी।

नरेला और पालम तक बढ़ेगी मेट्रो की पहुंच

12.9 किलोमीटर लंबा समयपुर बादली-नरेला कॉरिडोर मौजूदा येलो लाइन का विस्तार होगा। इस पर आठ एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है। इससे नरेला को और जाने वाले यात्रियों को मेट्रो की सुविधा मिलेगी। वहीं, 9.9 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर ब्लू लाइन का विस्तार होगा। इस पर छह स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें पांच भूमिगत होंगे। इससे इस रूट के आसपास रहने वाले लोगों को मेट्रो तक पहुंच बेहतर होगी।

जोर बाग-मिठापुर और मयूर विहार-शास्त्री पार्क कॉरिडोर

करीब 17 किलोमीटर लंबे जोर बाग-मिठापुर कॉरिडोर पर 12 स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है। इससे खान पहुंचना होगा। वहीं, 13.2 किलोमीटर लंबे मयूर विहार फेज-जीरो-सबसे पार्क कॉरिडोर पर आठ स्टेशन होंगे। कॉरिडोर में करीब नौ किमी भूमिगत हिस्सा शामिल होगा।

रोहिणी सेक्टर-34 तक पहुंचेगी मेट्रो

16.3 किलोमीटर लंबे केशवपुरम-रोहिणी सेक्टर-34 कॉरिडोर पर 12 एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं। इसके निर्माण से रोहिणी के नए इलाकों तक मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा और स्थानीय यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

रोहिणी से हरियाणा तक मेट्रो का विस्तार 26.46 किमी कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ा

संदीप वर्मा

नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के नरेला, बवाना और रोहिणी के लाखों लोगों को आने वाले समय में मेट्रो की बेहतर सुविधा का लाभ मिलेगा। दिल्ली से नरेला होते हुए हरियाणा के कुंडली तक बनने वाले 26.46 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर की निर्माण प्रक्रिया तेज हो गई है। परियोजना के तहत एलिवेटेड ट्रैक और स्टेशन बनाने के लिए 1373 करोड़ से अधिक के सिविल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया में है।

रिठाला-कुंडली कॉरिडोर से उन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जिन्हें अभी बसों या निजी वाहनों से लंबी दूरी तय करके मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है।

कॉरिडोर तैयार होने के बाद रोहिणी, बवाना, नरेला और कुंडली के बीच आवाजाही आसान होगी। खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और रोजाना दिल्ली-हरियाणा के बीच सफर करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। दीपावलीसरी ने कॉरिडोर के निर्माण को अलग-अलग पार्सलों में बांटा है। इनमें एक प्रमुख पार्सल के तहत करीब 15.4 किलोमीटर हिस्से में एलिवेटेड और जमीनी खाकाकार, रैंप, डिपो से संबंधी कार्य और 11 स्टेशनों का सिविल निर्माण होना है। इसकी अनुमानित लागत 1373.36 करोड़ रुपये है। 18 नवंबर तक इस चरण की निविदा जारी की गई है।

दूसरी ओर डिपो से 10 एलिवेटेड स्टेशनों और एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण के लिए भी निविदा प्रक्रिया चल रही है। परियोजना के तहत सराय डिपो के निर्माण का 138.70 करोड़ रुपये का टेंडर हो चुका है। कुल 21 स्टेशनों वाले इस कॉरिडोर को अनुमानित लगभग 6230.99 करोड़ रुपये है। परियोजना में इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

फैक्ट फाइल

- कॉरिडोर की लंबाई : 26.463 किलोमीटर
- कुल स्टेशन : 21
- कुल अनुमानित लागत : 6230.99 करोड़ रुपये
- प्रमुख सिविल पैकेज : 1373.36 करोड़ रुपये
- डिपो निर्माण का आवंटे : 138.70 करोड़ रुपये
- निर्धारित पूरा करने का लक्ष्य : मार्च 2029

1373
करोड़ रुपये के सिविल निर्माण की निविदा जारी

बिजली की लाइनों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया

इसके अलावा बिजली की 66 केवी और 400 केवी लाइनों को स्थानांतरित करने से संबंधित काम के लिए भी निविदाएं जारी की गई हैं। इसके प्रमुख निर्माण कार्य के दायरे में आने वाली बाधाओं को दूर करने की तैयारी है।

रिठाला-कुंडली कॉरिडोर रेड लाइन का होगा विस्तार

रिठाला-कुंडली कॉरिडोर रेड लाइन का विस्तार होगा। इससे दिल्ली और हरियाणा के बीच एक और मेट्रो संपर्क स्थापित होगा। यात्रियों को बसों और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलेगा। इससे बवाना और सोनीपत जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ेगी।

राजस्थान पत्रिका
(19 नवंबर, 2026)

पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान

नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और शहरी पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में बेहतर काम के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य को प्रतिष्ठित पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया है। राज्य के साथ बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा नगरीय निकायों को भी इस योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव ईशा कालिया ने छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र भेजकर इस चयन की जानकारी दी है। मंत्रालय ने योजना के सफल क्रियान्वयन में राज्य सरकार और नगरीय निकायों की भूमिका की सराहना करते हुए इसे सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ में 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने राज्य सरकार और संबंधित नगरीय निकायों के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबार से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देना है।

हरिभूमि
(19 नवंबर, 2026)

पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान बिलासपुर-बड़े बचेली, दंतेवाड़ा पुरस्कार के लिए चयनित

स्ट्रीट वेंडर्स के आर्थिक सशक्तीकरण और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मिली राष्ट्रीय पहचान, 20 नवंबर को दिल्ली में होगा सम्मान समारोह

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और शहरी पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य को प्रतिष्ठित पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया है। राज्य के साथ बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा नगरीय निकायों को भी इस योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव ईशा कालिया ने 16 नवंबर को छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र भेजकर इस चयन की जानकारी दी है। मंत्रालय ने योजना के सफल क्रियान्वयन में राज्य सरकार और नगरीय निकायों की भूमिका की सराहना करते हुए इसे सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ में 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने राज्य सरकार और संबंधित नगरीय निकायों के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबार से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देना है। छत्तीसगढ़ और उसके तीन नगरीय निकायों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन राज्य में शहरी आजीविका और पथ विक्रेताओं के सशक्तीकरण के प्रयासों को मिली महत्वपूर्ण पहचान है।

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

द पायनियर
(15 नवंबर, 2026)

कल से चलेंगी नमो भारत की आठ ट्रेनें

आनंद विहार से गाजियाबाद का सफर सिर्फ 8 मिनट में

एजेंसी। नई दिल्ली



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) 16 नवंबर से सुबह और शाम के व्यस्त समय के दौरान नमो भारत ट्रेन की आठ अतिरिक्त तेज सेवाएं शुरू करेगा, जिससे आनंद विहार और गाजियाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर महज आठ मिनट रह जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एनसीआरटीसी ने बताया कि कम स्टेशनों पर रुकने वाली ये ट्रेनें दिल्ली-मेरठ गलियारे पर चलेंगी। इनके जरिये आनंद विहार से बेगमपुल तक की दूरी 36 मिनट में और गाजियाबाद से बेगमपुल तक की दूरी 28 मिनट में तय की जा सकेगी। पूरे गलियारे की यात्रा 50 मिनट से भी कम समय में पूरी होगी। उसने बताया कि यात्रा का समय कम करने के लिए ये तेज ट्रेनें केवल पांच स्टेशनों- सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम पर रुकेंगी। इससे खासकर व्यस्त समय में सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को सुविधा होगी। सुबह के व्यस्त समय में सराय काले खां और मोदीपुरम से दोनों दिशाओं में दो-दो ट्रेनें सुबह आठ बजे और साढ़े आठ बजे रवाना होंगी। वहीं, शाम को दोनों टर्मिनल स्टेशनों से अतिरिक्त ट्रेनें छह बजे और साढ़े छह बजे चलेंगी। आठ अतिरिक्त ट्रेनें नियमित नमो भारत सेवाओं के साथ संचालित होंगी। नियमित ट्रेनें पहले की तरह हर 10 मिनट के अंतराल पर चलती रहेंगी। इससे मौजूदा ट्रेन सेवाओं की आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। एनसीआरटीसी के अनुसार, इस गलियारे पर फिलहाल रोजाना करीब 1.1 लाख यात्री सफर करते हैं और अब तक कुल पांच करोड़ यात्राओं का आंकड़ा पार हो चुका है। पिछले तीन महीनों में इस गलियारे पर हर महीने औसतन 32 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। एनसीआरटीसी ने बताया कि वायु प्रदूषण बढ़ने के बीच इन अतिरिक्त सेवाओं का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और पूरे क्षेत्र में सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना भी है।

वीर अर्जुन
(18 नवंबर, 2026)

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठा कर सशक्त हो रहे छोटे कारोबारी

चंडीगढ़, (पवन आश्री)। छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से रेहड़ी, पटरी, ठेला और फेरी लगाकर आजीविका कमाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

एक सरकारी प्रवक्ता नेबताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें अपने व्यवसाय को मजबूत बनाने के अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण दिया जाता है, जिससे वे अपनी जरूरत के अनुसार कारोबार में निवेश कर सकें और अपनी आजीविका को बेहतर बना सकें।

उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2020 को की गई थी। छोटे कारोबारियों को अधिक सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 तक कर दी गई है। इसके साथ ही योजना के तहत ऋण की पहली और दूसरी किस्त की सीमा में भी वृद्धि की गई है। अब पहली किस्त के तहत 10,000 रुपये के स्थान पर 15,000 रुपये तक और दूसरी किस्त के तहत 20,000 रुपये के स्थान पर 25,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं, तीसरी किस्त के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

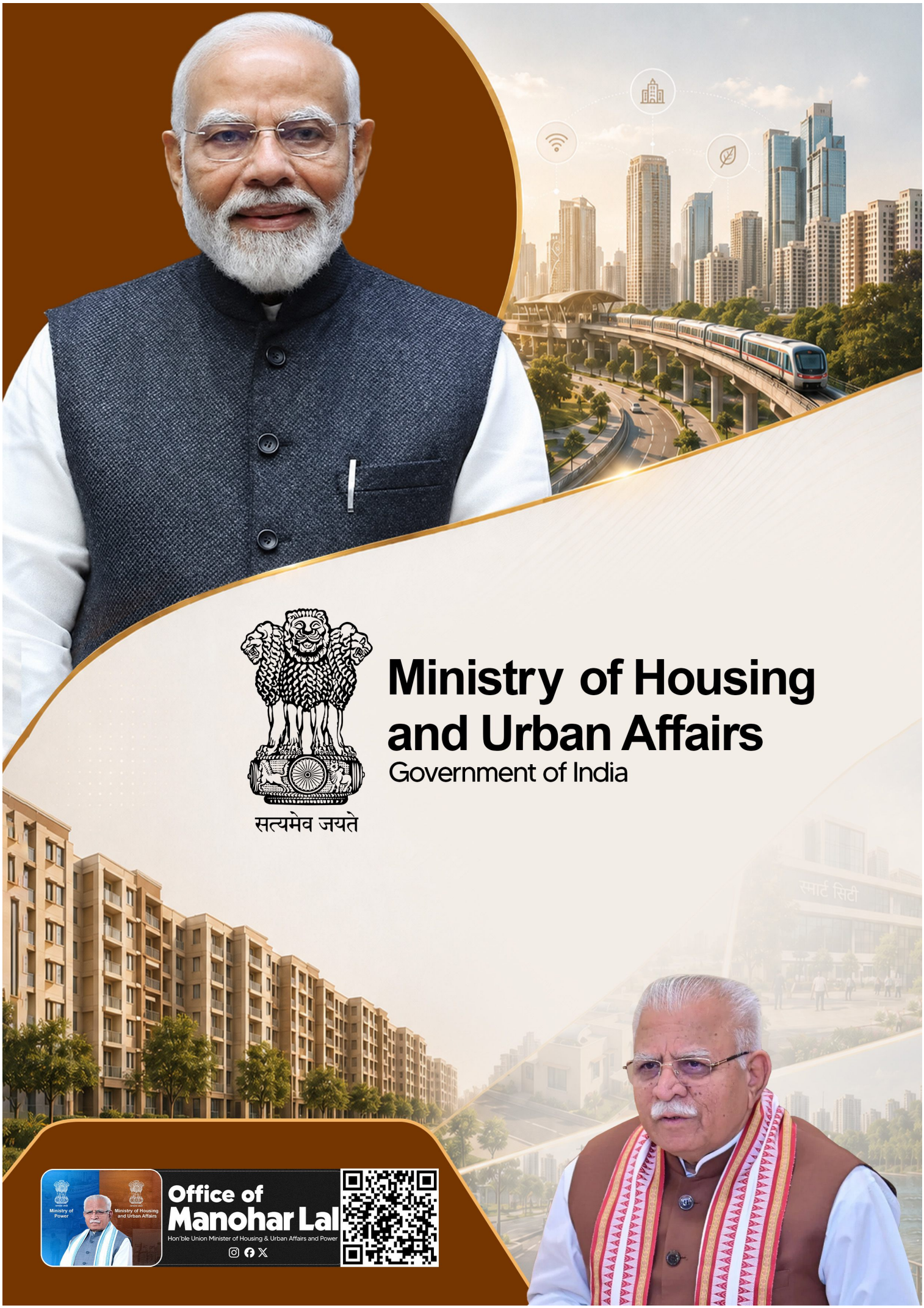
सत्यमेव जयते
Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India
Office of
Manohar Lal
Hon'ble Union Minister of Housing & Urban Affairs and Power
Ministry of Power
Ministry of Housing and Urban Affairs